

निजी इक्विटी व वीसी निवेश बढ़ा

जुलाई में सालाना आधार पर 3% बढ़कर 4.1 अरब डॉलर हुआ

नवभारत न्यूज नेटवर्क मुंबई, 01 सितम्बर. भारत में निजी इक्विटी (पीई) और उद्यम पूंजी (वीसी) कोषों का निवेश जुलाई में सालाना आधार पर तीन प्रतिशत बढ़कर 4.1 अरब डॉलर हो गया. सलाहकार कंपनी ईवाई और उद्योग संगठन आईवीसीए की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

जुलाई, 2025 में चार अरब डॉलर का निवेश हुआ था. जुलाई, 2026 में निवेश जून के 2.7 अरब डॉलर की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक रहा. इसमें कहा गया कि जुलाई, 2026 में सौदों की संख्या 111 रही, जो जुलाई, 2025 के 119 सौदों की तुलना में

PE/VC निवेश के प्रमुख आंकड़े			
सूचकांक	जुलाई 2026	जुलाई 2025	बदलाव
कुल PE/VC निवेश	4.1 अरब डॉलर	4.0 अरब डॉलर	+3%
सौदों की संख्या	111	119	-7%
बड़े सौदे	10	—	—
बड़े सौदों का कुल मूल्य	2.8 अरब डॉलर	—	कुल निवेश का 68%
निकासी सौदे	17	26	—
निकासी का कुल मूल्य	1.6 अरब डॉलर	9.2 अरब डॉलर	—
फंड जुटाना	2.5 अरब डॉलर	1.5 अरब डॉलर	+67%

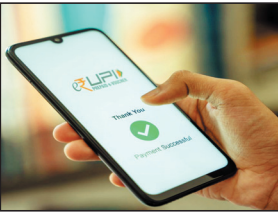
जुलाई, 2026 में पीई/वीसी गतिविधियों में खरीद सौदों से जुड़े निवेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही. इस श्रेणी में 1.4 अरब डॉलर का निवेश किया गया जो जुलाई, 2025 में किए गए 51.1 करोड़ डॉलर के निवेश से 176 प्रतिशत अधिक है. इसके बाद ऋण निवेश का स्थान रहा जिसमें 88 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश हुआ.

सात प्रतिशत कम है. इससे सौदे के आकार में वृद्धि का संकेत

मिलता है. जुलाई में हुए सौदों की संख्या जून, 2026 के 80 सौदों से

काफी अधिक रही.

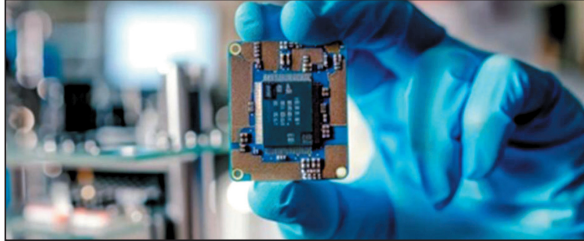
सौदों की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद- भारत की व्यापक आर्थिक बुनियाद निवेश गतिविधियों के लिए अनुकूल बनी हुई है. पीई/वीसी (निजी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी) कोष के पास बड़ी मात्रा में निवेश योग्य धन उपलब्ध होने से भू-राजनीतिक परिस्थितियों के स्थिर होने के साथ सौदों की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है. जुलाई, 2026 में 10 बड़े सौदे हुए जिनका कुल मूल्य 2.8 अरब डॉलर रहा. यह कुल निवेश गतिविधियों का करीब 68 प्रतिशत था. इसमें बुकफोल्ड का लुमारा में 60 करोड़ डॉलर का निवेश सबसे बड़ा रहा.



बिना इंटरनेट होगा यूपीआई भुगतान

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 01 सितम्बर. डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने सोमवार को 'फोनपे यूपीआई 123पे' सेवा शुरू करने की घोषणा की, जिसके जरिए फीचर फोन उपयोगकर्ता भी इंटरनेट कनेक्शन के बगैर यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे. कंपनी ने दावा किया कि इस सेवा के साथ वह फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई भुगतान की सुविधा देने वाली पहली प्रमुख टीपीएपी कंपनी बन गई है. इस समय देश में 20 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ता होने का अनुमान है.

बढ़ेगी भारत की चिप की ताकत



उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को मिलेगा वित्तीय सहयोग

सेमीकॉन 2.0 के तहत सेमीकंडक्टर उद्योग के अलग-अलग बॉटिकल में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन के अलावा पैकेजिंग तथा सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं. सरकार का फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने तक सीमित नहीं है. योजना के तहत सेमीकंडक्टर की पूरी वैल्यू चेन में घरेलू क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया गया है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार एक हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल गठित करेगी.

गया है. इनमें भारतीय कंपनियों द्वारा सेमीकंडक्टर डिजाइन, चिप निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल इक्विपमेंट का उत्पादन,

सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनियट्स और चिप असेंबली, पैकेजिंग एवं टेस्टिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

15 साल बाद टिम कुक ने छोड़ी एप्पल सीईओ की कुर्सी

- जॉन टर्नस को मिली कमान
- अब एजीक्यूटिव चेयरमैन होंगे कुक



कैलिफोर्निया, 1 सितंबर: एप्पल में लंबे समय बाद बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। अगस्त 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने टिम कुक ने 15 साल की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद सीईओ पद छोड़ दिया. अब वह एप्पल के एजीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे. उनकी जगह जॉन टर्नस ने कंपनी के नए सीईओ का पद संभाल लिया है.अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कुक ने

एप्पल कर्मचारियों को संदेश भेजकर उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह कंपनी से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस भूमिका से पीछे हट रहे हैं जिसे उन्होंने लंबे समय तक पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया. कुक ने यह भी कहा कि कर्मचारियों का नेतृत्व करना उन्हें याद आएगा, लेकिन टर्नस को जिम्मेदारी सौंपने को लेकर वह आश्चर्य है. कुक ने सीशल मीडिया मंच एक्स पर भी अपने विदाई संदेश में एप्पल समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया.

यूपी-बिहार में भी अब जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

दिल्ली-मुंबई से छोटें शहरों तक ऐसे बदलेगा साफर शहरों से जोड़ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम कर रहा रहेगे

नवभारत न्यूज नई दिल्ली, 1 सितंबर. उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों के लिए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को लेकर बड़ी योजना सामने आई है. केंद्र सरकार दिल्ली को उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम कर रही है. प्रस्तावित परियोजना के तहत दिल्ली से लखनऊ की यात्रा करीब दो घंटे और पटना तक का सफर लगभग 4.5 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल मार्ग में आगरा, कानपुर, लखनऊ,

प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों को शामिल करने की योजना है. इससे राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के इन महत्वपूर्ण केंद्रों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो सकता है.बताए गए अनुमान के मुताबिक, दिल्ली से आगरा की करीब 200 किलोमीटर दूरी लगभग 58 मिनट में पूरी हो सकती है. वहीं करीब 455 किलोमीटर दूर कानपुर पहुंचने में लगभग 1 घंटे 50 मिनट का समय लगने का अनुमान है. दिल्ली से लखनऊ की करीब 495 किलोमीटर यात्रा लगभग 2 घंटे 12 मिनट में पूरी करने का लक्ष्य बताया गया है.इसी तरह प्रस्तावित नेटवर्क में दिल्ली से प्रयागराज तक करीब तीन घंटे और वाराणसी तक लगभग 3 घंटे 33 मिनट का समय लग सकता है.

यह परियोजना देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. फिलहाल भारत में सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जबकि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना देश की पहली वास्तविक बुलेट ट्रेन सेवा के रूप में विकसित की जा रही है. मुंबई-अहमदाबाद परियोजना की डिजाइन गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे और परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित है.

समाचार विशेष

केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सियासी भूचाल !

चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर की

लखनऊ, 1 सितंबर. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बस कुछ महीनों का वक्त बचा है. इससे पहले राज्या में सियासी लड़ाई तेज हो गई है. सभी पार्टियां एक-दूसरे पर वार.पलटवार कर रही हैं. इस बीच भाजपा में अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आती दिख रही है. 2017 में प्रचंड बहुमत के बाद सीएम पद की रेस में आगे दिख रहे केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी से संतोष करना पड़ा था. इस बार चुनाव से पहले ही उन्होंने खुलकर मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हो सकता

2027 में 300 सीटें जीतने का दावा



हमारी सरकार ने निष्पक्ष होकर काम किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नोकियाय भी दी है तो हर वर्ग का ख्याल रखते हुए दी है. केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर भी दावा किया कि भाजपा को करीब 300 सीटें मिलेंगी. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी ताल का हसीन सपना देख रहे हैं, जो चुनाव के बाद चूर-चूर हो जाएगा.

केशव प्रसाद मौर्य ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही. दोनों नेताओं के बीच प्रतियक्षा को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं. सीएम और डिप्टी सीएम मिलकर काम करते हैं और यही कारण है कि हम लगातार सता में बने हुए हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी दावा किया कि विकसित भारत बनने तक राज्य में सपा और देश में कांग्रेस के हाथों में सता नहीं जाएगी. केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने निष्पक्ष होकर काम किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नोकियाय भी दी है तो हर वर्ग का ख्याल रखते हुए दी है. केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर भी दावा किया कि भाजपा को करीब 300 सीटें मिलेंगी. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी ताल का हसीन सपना देख रहे हैं, जो चुनाव के बाद चूर-चूर हो जाएगा.

है कि अगली बार आप मुख्यमंत्री के रूप में देखें या फिर किसी और रूप में देखें. उन्होंने कहा कि यह तो पार्टी तय करेगी, मेरी महत्वाकांक्षा से ही कुछ तय नहीं होगा. उन्होंने खुलकर कहा कि मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं. लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि कौन क्या करेगा. उन्होंने फिलहाल 2027 में बहुमत से जीतने को अपना लक्ष्य बताया है. उन्होंने कहा कि इसके बाद विधायक दल तय करेगा और दिल्ली से आने वाले पर्यवेक्षक तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा.

जातिगत राजनीति में खड़ी है भाजपा



लखनऊ, 1 सितंबर. हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण विरोधी युवाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंच साझा किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनुस्मृति के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा.

ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि यूपी में चुनाव से पहले हो रही जातिगत राजनीति में बीजेपी कहां

कोर वोटर सर्वर्णों सहित 3 मुद्दों से निपटने की चुनौती

खड़ी है? क्या अब उसको अपने कोर वोटर सर्वर्णों की चिंता सता रही है? जातिगत संतुलन बनाने के लिए पार्टी की क्या रणनीति है? आरक्षण व्यवस्था के विरोध में शुरू हुई मुहिम को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. हर्ष दुबे

बीजेपी की ये हे कोशिश

बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और संघ में लगातार यह मंथन चल रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जाति के पलटों में जा रही राजनीति का क्या समाधान निकाला जाए. ऐसे में बीजेपी नेतृत्व की कोशिश यह है कि ओबीसी और दलितों को भी साधा जाए और कोर सर्वर्ण वोटर भी उससे न छिटके. यही वजह है कि दलितों और ओबीसी को पूरा सम्मान देने के साथ ही वह सर्वर्णों के साथ भी खड़ी दिखना चाहती है. वहीं मनुस्मृति को विरासत से जोड़कर चुनाव की जातीय खांचे से निकालकर धार्मिक रूप देने की भी है.

सपा से सीट बंटवारे का मोर्चा प्रमोद तिवारी ने सम्हाला ?

लखनऊ, 1 सितंबर. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले. उनके साथ उनकी बेटी और कांग्रेस विधायक दल की नेता अनुराधा मिश्रा भी थीं. गौरतलब है कि यूपी में कांग्रेस के दो ही विधायक हैं, जिनमें एक प्रमोद तिवारी की बेटी हैं.

प्रमोद तिवारी भले प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा माना जाता है. पार्टी के शीर्ष नेताओं को उनके ऊपर भरोसा है. इसलिए अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल पर चर्चा कर रहे हैं? यह संभव है क्योंकि प्रदेश संगठन के बाकी नेताओं से अखिलेश यादव सीट बंटवारे की बात नहीं

करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों या नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम हों उनके साथ अखिलेश बात नहीं करेंगे. हां, बाद में बातचीत में ये लोग शामिल हो सकते हैं. तभी संभव है कि सीट बंटवारे की प्राथमिक बातचीत प्रमोद तिवारी ने की है.

यह भी हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा की ओर से कोई संदेश लेकर वे गए हैं. ध्यान रहे इमरान मसूद जैसे कई कांग्रेस नेता सपा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं. सपा की ओर से 80 लोकसभा सीटों के हिसाब से 80 सीट कांग्रेस को देने का प्रस्ताव है. कांग्रेस 2017 के फॉर्मूले से एक सौ करीब सीट मांग रही है. दोनों पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि सीटों की संख्या से ज्यादा क्वालिटी सीट पर मामला अटकेगा. लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां जल्दी सीट बंटवारा चाहती हैं.



विशेष पीएम चेहरे पर तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके आमने-सामने

राहुल गांधी या सीएम विजय ...

चेन्नई, 1 सितंबर. तमिलनाडु सरकार में मंत्री एस. राजेश कुमार ने कांग्रेस और टीवीके गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलनाा वेवी कझगम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार नहीं करती है, तो कांग्रेस के दोनों मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे.

कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम के दौरान राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस 2029 में प्रधानमंत्री पद के



उम्मीदवार लिए राहुल गांधी के नाम को समर्थन देगी. उनका दावा है कि राहुल गांधी देश के अगले पीएम बनने जा रहे हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी. राजेश कुमार के साथ पी. विश्वनाथ



कांग्रेस के दो नेता विजय सरकार में मंत्री हैं. गौरतलब है कि तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन के कई सहयोगी और टीवीके के नेता मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को 2029 के लोकसभा चुनाव के

लिए पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं. इसी बीच राजेश कुमार का बयान कांग्रेस और टीवीके के बीच बढ़ते मतभेद के तौर पर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन सहयोगी राहुल गांधी की उम्मीदवारी को सपोर्ट नहीं करते, तो वह और पी. विश्वनाथन दोनों कैबिनेट से अगल हो सकते हैं.

बताते चलें कि 4 मई 2026 को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था.

राहुल गांधी के समर्थन में वाइकू

तमिलनाडु सरकार में शामिल एक अन्य सहयोगी दल रक्ख के प्रमुख वाइकू ने राहुल गांधी के नाम पर अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस ब्रह्मष्ट्र अलायंस को लीड कर रही है, इसलिए राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता. वाइकू ने सीएम विजय को सुझाव दिया है कि वे अपने मंत्रियों के बेतुके दावे पर तुरंत लगाम लगाएं. तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं.